Newspaper Clips

June 23, 2011

Jansatta ND 23/06/2011 P-9

आईआईटी छात्रों की पहली पसंद मुंबई और दूसरी दिल्ली

कानपुर, 22 जून(भाषा)। इस बार की आईआईटी संयुक्त प्रवेश परीक्षा(आईआईटी जेइई 2011) कराने वाली आईआईटी कानपुर ने सफल अभ्यर्थियों की काउंसलिंग का परिणाम घोषित कर दिया है और सफल छात्रों की पहली पसंद आईआईटी मुंबई रही जबकि दूसरे नंबर पर छात्रों ने आईआईटी दिल्ली को चुना, छात्रों की पहली पसंद कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग रही।

आईआईटी कानपुर की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक जेईई 2011 की परीक्षा में कुल 13 हजार 197 छात्र सफल हुए थे इनमें से 9319 को पहले चरण की काउंसलिंग में सीट मिल गई और सबसे ज्यादा छात्रों ने आईआईटी मुंबई को अपनी पहली पसंद बनाया। परीक्षा में सफल सौ शीर्ष छात्रों में से 70 छात्रों ने आईआईटी मुंबई, 24 छात्रों ने आईआईटी दिल्ली, चार छात्रों ने आईआईटी कानपुर और दो छात्रों ने आईआईटी मद्रास को चुना। इसी तरह प्रथम सौ छात्राओं में से 27 ने आईआईटी मुंबई, 26 ने आईआईटी दिल्ली, 12 ने आईआईटी खड़गपुर, 11 ने आईआईटी कानपुर, 18 ने आईआईटी मद्रास और छह छात्राओं ने आईआईटी रूड़की को अपनी पहली पसंद बनाया। इसी तरह अगर विषय की बात करें तो पहले दौर की काउंसलिग में सबसे ज्यादा 3352 छात्र छात्राओं ने कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग को चुना, 1393 ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को अपनी पहली पसंद बनाया । इसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग और एयरोस्पेस इंजीनियरिंग को छात्र छात्राओं ने अपनी पसंद बनाया।

अगर विषय की बात करें तो यहां भी आईआईटी मुंबई नंबर एक पर रहा और सबसे ज्यादा छात्र छात्राओं ने आईआईटी मुंबई के कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग को अपनी पहली पसंद बताया जबकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में प्रवेश चाहने वाले छात्र छात्राओं की पहली पसंद भी आईआईटी मुंबई ही रही। काउंसलिंग के दौरान आईआईटी मुंबई के कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग को 3352 छात्र छात्राओं ने अपनी पहली पसंद बनाया, जबकि आईआईटी मुंबई के ही इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को 1393 छात्र छात्राओं ने अपनी पहली पसंद बताया।

आईआईटी दिल्ली के कंप्यूटर विज्ञान और प्रौद्योगिकी को 964 छात्र छात्राओं ने अपनी पहली पसंद, आईआईटी मुंबई के मैकेनिकल इंजीनियरिंग को 784 छात्र छात्राओं ने अपनी पहली पसंद और आईआईटी मुंबई के एयरोस्पेस इंजीनियरिंग को 415 छात्र छात्राओं ने अपनी पहली पसंद बनाया।

आईआईटी के बयान के मुताबिक दस अप्रैल को हुई परीक्षा में देश के 1051 केंद्रों पर जेईई 2011 की परीक्षा हुई थी जिसमें चार लाख 68 हजार 240 परीक्षार्थी परीक्षा में बैठे थे जिनमें 13 हजार 197 परीक्षार्थी सफल घोषित किए गए थे। इसमें से 9319 को पहले चरण की काउंसलिंग में सीट मिली है। इनमें से भी 1382 छात्र छात्राओं को अपनी मनपसंद पहली सीट और संस्थान ही मिला है। आईआईटी काउंसलिंग में सीट पाने वाले छात्र छात्राओं से 28 जून तक अपने अपने संस्थान में रिपोर्ट करने को कहा गया है और इस दौरान रिपोर्ट कर फीस न जमा की गयी तो सीट खाली मानी जाएगी।

Punjab Kesari ND 23/06/2011 P-9

आईआईटी छात्रों की पहली पसंद बनी मुंबई व दूसरी दिल्ली

■ विराट न्यूज।

कानपुर। इस बार की आईआईटी संयुक्त प्रवेश परीक्षा (आईआईटी जेईई 2011) कराने वाली आईआईटी कानपुर ने सफल अभ्यर्थियों की काउंसलिंग का परिणाम घोषित कर दिया है और सफल छात्रों की पहली पसंद आईआईटी मुंबई रही जबकि दूसरे नंबर पर छात्रों ने आई आई टी दिल्ली को चुना, छात्रों की पहली पसंद कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिग रही।

आईआईटी कानपुर द्वारा जारी एक बयान के अनुसार जेईई 2011 की परीक्षा में कुल 13 हजार 197 छात्र सफल हुए थे इनमें से 9319 को पहले चरण की काउसंलिग में सीट मिल गई और सबसे ज्यादा छात्रों ने आई आई टी मुंबई को अपनी पहली पसंद परीक्षा में सफल.100 शीर्ष छात्रों में से 70 छात्रों ने आई आई टी मुंबई, 24 छात्रों ने आईआईटी दिल्ली, चार छात्रों ने आईआईटी कानपुर तथा दो छात्रों ने आई आई टी मद्रास को चुना।

इसी तरह प्रथम 100 छात्राओं में से 27 ने आईआईटी मुंबई, 26 ने आईआईटी दिल्ली, 12 ने आईआईटी खड़गपुर, 11 ने आईआईटी कानपुर, 18 ने आईआईटी मद्रास तथा छह छात्राओं ने आईआईटी रूड़की को अपनी पहली पसंद बनाया। इसी तरह अगर विषय की बात करें तो पहले दौर की काउसंलिग में सर्वाधिक 3352 छात्र छात्राओं ने कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग को चुना, 1393 ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को अपनी पहली पसंद बनाया।

इसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग और एयरोस्पेस इंजीनियरिंग को छात्र छात्राओं ने अपनी पसंद बनाया। अगर विषय की बात करें तो यहां भी आईआईटी मुंबई नंबर एक पर रहा और सबसे ज्यादा छात्र छात्राओं ने आईआईटी मुंबई के कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग को अपनी पहली पसंद बताया जबकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में प्रवेश चाहने वाले छात्र छात्राओं की पहली पसंद भी आईआईटी मुंबई ही रही। काउंसलिंग के दौरान आईआईटी मुंबई के कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग को 3352 छात्र छात्राओं ने अपनी पहली पसंद बनाया, जबकि आईआईटी मुंबई के ही इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को 1393 छात्र छात्राओं ने अपनी पहली पसंद बताया।

आईआईटी दिल्ली के कंप्यूटर विज्ञान और प्रौद्योगिकी को 964 छात्र छात्राओं ने अपनी पहली पसंद, आईआईटी मुंबई के मैकेनिकल इंजीनियरिंग को 784 छात्र छात्राओं ने अपनी पहली पसंद तथा आईआईटी मुंबई के एयरोस्पेस इंजीनियरिंग को 415 छात्र छात्राओं ने अपनी पहली पसंद बनाया। आईआईटी द्वारा जारी बयान के अनुसार दस अप्रैल को हुई परीक्षा में देश के 1051 केंद्रों पर जेईई 2011 की परीक्षा हुई थी जिसमें चार लाख 68 हजार 240 परीक्षार्थी परीक्षा में बैठे थे जिनमें 13 हजार 197 परीक्षार्थी सफल घोषित किए गए थे। इसमें से 9319 को पहले चरण की काउंसलिंग में सीट मिली है।

इनमें से भी 1382 छात्र छात्राओं को अपन मनपसंद पहली पसंद की सीट और संस्थान ही मिला है। आईआईटी काउंसलिंग में सीट पाने वाले छात्र छात्राओं से 28 जून तक अपने अपने संस्थान में रिपोर्ट करने को कहा गया है और इस दौरान रिपोर्ट कर फीस न जमा की गई तो सीट खाली मानी जाएंगी।■

Business Standard ND 23/06/2011 P-10

GMAT candidates from India have doubled in 4 years

GRADUATE Management Admission Council (GMAC), which opened its India office this February, is looking to grow its GMAT volumes in India and get more B-schools to start using the format as part of their admission process. In the first four months, India has seen a 10 per cent jump in the number of students appearing for the GMAT exam over the same period last year. DAVID A WILSON, President and CEO, GMAC, tells Praveen Bose and Pradeesh Chandran why he is bullish on India. Edited Excerpts:

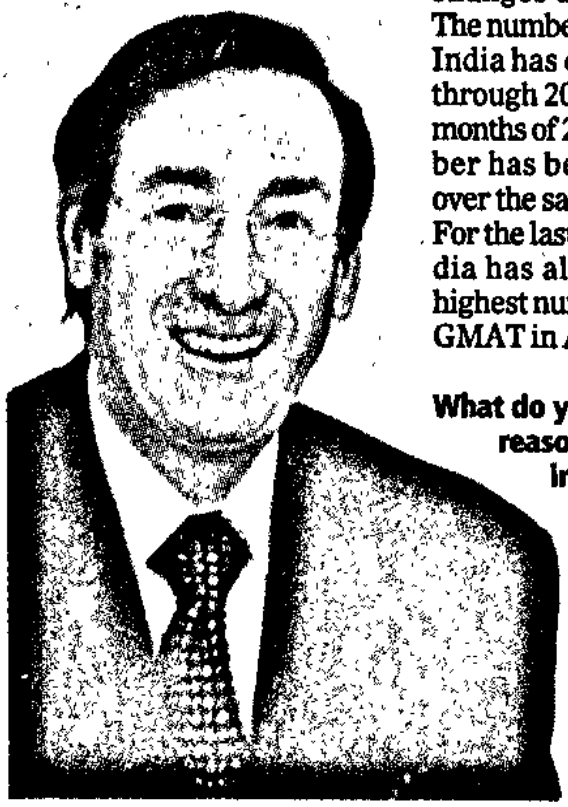

Q&A

DAVID A WILSON
President & CEO,
Graduate Management
Admission Council (GMAC)

Why are you so bullish on the India market?

The last five years have been very eventful for GMAC in India. It has seen incredible changes during this period. The number of test takers from India has doubled from 2006 through 2010. In the first four months of 2011 alone, the number has been up 10 per cent over the same period last year. For the last five years or so, India has also seen one of the highest numbers taking up the GMAT in Asia.

What do you think is the reason behind the increase in numbers of GMAT takers from India?

There are three factors that have contributed to the growth. The value that India is placing towards higher education, technology driving cutting-edge technology, and spirit of entrepreneurship that encourages entrepreneurship. A prominent trend that the GMAC has witnessed lately is that Indians are now looking at studying in India, as the country has some very good business schools. And, the GMAC products facilitate the platform to connect students to global B-schools. The GMAT gives candidates more choices.

How has GMAC dealt with examination malpractice to improve its credibility?

GMAC is using advanced techniques to root out malpractice. For instance, the GMAT employs the most advanced test security programme in the industry, including palm vein technology to verify the identity of test takers. The GMAT is the only high-stakes admissions test capable of identifying serial proxy test takers.

How does GMAT stand out from similar tests?

GMAC opens doors for Indian students as schools across the globe accept GMAT scores for five years. Hence, they do not need to prepare for the exam every year. That's the value proposition which can be very enticing for those taking the test.

Business Standard ND 23/06/2011 P-10

B-SCHOOLS SEE RED OVER IIM-A'S PLACEMENT REPORTING NORMS

Smaller institutes worry their students may further lose out on placement opportunities

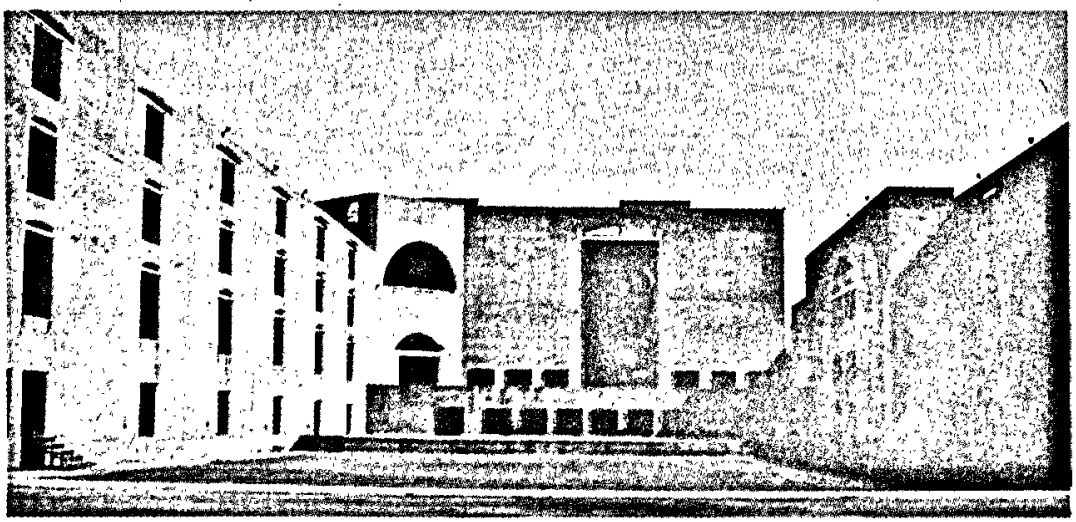

IIM-A had proposed to standardise placement reporting norms across B-schools to bring transparency and uniformity

VINAY UMARJI

The Indian Institute of Management Ahmedabad's (IIM-A) attempt to bring in more transparency with a new placement reporting standard, has left tier-3 B-schools in India worried.

B-schools that score low on critical parameters – infrastructure, intellectual capital, industry interface and placements – are termed tier-3 B-schools. Such attempts may result in tier-3 management institutes losing out in placements to large- and mid rung B-schools and could widen the ranking gap between them, said B-schools.

"Traditionally, recruiters have preferred better performing and top B-schools against the smaller ones. Recently, a recruiter firm came to our campus only because it couldn't get students from a top institute in our region. Once the placement reporting standards are implemented, such a scenario may aggravate and smaller institutes may lose out more in the long run," said Sanjeev Bajaj, chief coordinator, placements and corporate relations of Ranchi based, Xavier Institute of Social Service.

Echoing similar views, Hema Sisodia, dean, corporate relations and campus placements, IBS Mumbai said: "If the salaries for some B-schools are currently high, more transparency will attract more recruiters to those B-schools. If the salaries are low and variable compensation are not reflecting, then the smaller B-schools may lose out. Corporates are willing to respond to only better institutes."

THE PREMIER INSTITUTE DECIDED TO DO AWAY WITH THE CONCEPT OF CTC and instead, focus on maximum earning potential (MEP) that would include cash, non-cash and other variable components

Last February, IIM-A had proposed to introduce placement reporting norms with the objective of bringing in transparency and uniformity in the manner in which B-schools report campus placements.

Last week, many B-schools, led by IIM-A, decided to do away with the concept of cost-to-company (CTC). Instead, B-schools would now look to declare a maximum earning potential (MEP) that would include cash, non-cash and other variable components.

IIM-A was of the opinion that CTC did not reflect the guaranteed cash component and gave a wrong picture about variable components, and said that reporting the total guaranteed cash components and MEP separately will provide sufficient meaningful information.

Among other B-schools which were apprehensive about losing out to competition are Pune-based Kirloskar Institute of Advanced Management Studies (KIAMS) and Goa Institute of Management.

"The moment a B-school states its salary structure, it defines its position in the market. As far as students and recruiters are concerned, everyone would like to move to the better performing ones. This is where the low rung B-schools will lose out. In fact, I also have doubts on how many institutes will go for the standards. The gap will only widen," said R Nagarajan, associate professor, finance, Goa Institute of Management.

Rating agency Crisil, which has been grading B-schools for a year, however, chooses to disagree with the B-schools. It said B-schools will have an enhanced ability to generate trust with the student community and with recruiters, adding that the standards are still at a nascent stage and their acceptance remains to be seen.

"Leaders of B-schools are likely to be the first to adopt these standards. However, such measures of transparency, must not be viewed in the context of creating or widening gaps within the sector but more as an industry initiative to unite and self regulate. Once B-schools adopt these standards, it will make the sector more transparent, with respect to employment data and facilitate comparability. Tier-3 business schools can also choose to utilise these standards to showcase their commitment to transparency," saids Hetal Dalal, Head-Ratings, Crisil.

IIM-A said such fears are unfounded. According to the institute, if B-schools focus on quality education than figures, which are misreported at present, they need not worry. Moreover, by focusing on quality education and building a strong alumni base, even low-rung B-schools can improve their positions.

"Placement reporting standard is just the beginning in ushering in transparency but this needs to be backed up by quality education. I think the fears are baseless because there is too much emphasis on compensation packages being a performance criterion than quality education," said Saral Mukherjee, chairperson, placements at IIM-A.

Sisodia, however, has already worked out her strategy — focusing on maximum earning potential of the student. "The focus should be on maximum earning potential and how the variable portion of the package can be included to stay alive in the competition."

Dainik Jagaran ND 23/06/2011 P-1

अब आइआइटी पर टिकी लोड टेस्टिंग

फ्लाईओवर की मजबूती को लेकर सीवीसी ने आइआइटी के विशेषज्ञों से मांगी सलाह

- लोक निर्माण विभाग और केंद्रीय सतर्कता आयोग के बीच जारी है खींचतान
- राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन के लिए बनाए फ्लाईओवरों की मजबूती परखने का मामला
- पीडब्ल्यूडी का तर्क-निर्माण के दौरान ही हो चुकी है फ्लाईओवरों की लोड टेस्टिंग

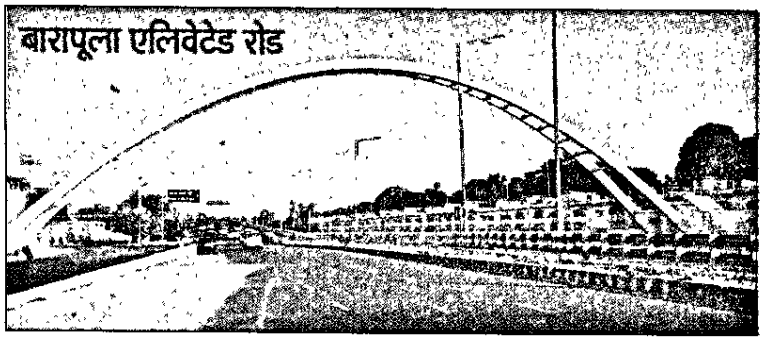

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता : राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन के लिए बनाए गए फ्लाईओवरों की लोड टेस्टिंग (जांच) हो या नहीं, इस पर आइआइटी के विशेषज्ञ फैसला देंगे। अभी इस मामले पर लोक निर्माण विभाग और केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के बीच खींचतान है। लोक निर्माण विभाग लोड टेस्टिंग कराने का मना कर चुका है। उसने सीवीसी को लिखा है बारापूला सहित जिन पांच फ्लाईओवरों की लोड टेस्टिंग कराने की बात कही गई है, उनकी तो निर्माण के दौरान ही लोड टेस्टिंग हो चुकी है, क्योंकि निर्माण के दौरान ही इनके ऊपर जो भारी भरकम मशीनें लगाई गई थीं, उनका वजन ही बहुत अधिक था। ऐसे में अब कोई जरूरत नहीं है।

उधर सीवीसी के सूत्रों का कहना है कि योजनाओं की मजबूती और गुणवत्ता को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, उन्हें ऐसे ही नहीं नकारा जा सकता है। इसके लिए आइआइटी के विशेषज्ञों से राय ली जा रही है। यदि वे लोड टैस्टिंग की बात नकारते हैं, तो ही इस बारे में कोई फैसला लिया जाएगा। इस बारे में लोक निर्माण विभाग के निदेशक (कार्य) सुधीर कुमार का कहना है कि लोड टेस्टिंग का मामला सीवीसी के पास भेजा गया है। वहां से अभी कोई जवाब नहीं मिला है। शुंगलू कमेटी व सीवीसी ने खेलों की 26 योजनाओं पर सवाल उठाए हैं। इनमें लोक निर्माण विभाग के बारापूला एलीवेटेड रोड, नारायणा फ्लाईओवर, सलीमगढ़ बाईपास मार्ग, राजाराम कोहली मार्ग, गाजीपुर ग्रेड सेपरेटर योजना शामिल है। योजनाओं पर सवाल उठने के बाद कुछ माह पहले दिल्ली सरकार ने कहा था कि वह योजनाओं की लोड टेस्टिंग कराने को तैयार है, मगर बाद में फ्लाईओंवरों के निर्माण से जुड़े विशेषज्ञों ने सरकार को राय दी थी, कि लोड टेस्टिंग की कोई जरूरत नहीं है, इस पर पैसा खर्च करना धन की बर्बादी होगी। इस पर लोक निर्माण विभाग ने केंद्रीय सतर्कता आयोग को पत्र लिखा था कि लोड टेस्टिंग न कराई जाए। जिस पर सीवीसी की ओर से अभी तक जवाब नहीं आया है। सूत्रों का कहना है कि सीवीसी इस बारे में आइआइटी के विशेषज्ञों से राय ले रही है। विशेषज्ञ इन योजनाओं का तकनीकी अध्ययन करेंगे। इस बारे में वे जो भी निर्णय देंगे वही मान्य होगा।